

संक्षिप्त समाचार

नया बिजलीघर बनाना सरकार के वश में नहीं: अजितेश लखनऊ समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अजितेश यादव ने भीषण गर्मी के बीच उत्तर प्रदेश में व्याप्त बिजली संकट को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार पर तंज करते हुए कहा कि बिजली के नए प्लांट लगाना सरकार के वश में नहीं है। यादव ने एकत्र पर विस्था कि बिजली के नए प्लांट लगाना तो आपके बस में था नहीं, न ही आपकी तंग सोच में। मुझे से ये कह ही देते '3 गुना 660 सुपर क्रिडिकल थर्मल पावर प्लांट' तो मैंने बहुतसे प्रस्तावसिधियों को सुनकर ही थोड़ी राहत मिल जानी। उन्होंने कहा कि भाजपा के कानून में उम्र पर बिजली को सिर्फ 'मांग' बंद रही है या 'दाम' बंद रही है। सचलाई-आपूर्ति नहीं। भाजपा राज, यूपी खस्ताहाला। उन्होंने अपने संदेश के साथ स्मॉल नगर, लखनऊ, राजधानी, उत्तर प्रदेश शब्द भी जोड़े। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है और कई जिलों से बिजली कटौती की शिकायतें मिल रही हैं।

गंगा में स्नान करते समय बीयर पीने का वीडियो वायरल बाराणसी माफिक नगरी काशी में गंगा में स्नान करते समय एक युवक द्वारा बीयर पीने का मामला सुर्खियों में आया। शुक्रवार को 'ब नगर' पर एसीएसएन के वॉटर प्लांटक तलाश भारतीय जनता पार्टी जिल्हा प्रमुख के काशी क्षेत्र के संयोजक शोभा शोहर जिवाही ने देशावस्था प्रसारित को लिखित शिकायत कर सुधारमा दे कर उचित कार्रवाई की मांग की है। जिवाही ने बताया कि सुबह सोराव अकाउंटेंट एच रहें थे, एचपी एक वीडियो उठा कर सामने आए जिसमें एक युवक गंगा में स्नान करते हुए बीयर पी रहा है।

19 लोगों को गन लाइसेंस किस आधार पर दिए

शाह टाइम्स ब्यूरो

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बंदते गन कल्चर और हथियार लाइसेंस के दुर्प्रयोग पर बेहद सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि हथियारों का सांख्यिक प्रदर्शन समाज में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा करता है और इससे कानून का राज कमजोर होता है। यूपी सरकार सभी विलक्षण परिस्थितियों, पुलिस कमिश्नरों और एएसएमों से इस मामले में जवाब मांग गया है। कोर्ट ने पूछा कि आखिर ऐसे लोगों को लाइसेंस किस आधार पर दिए गए?

बैरब्रदर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले को सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रदेश में हथियार लाइसेंस व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। न्यायाधीश निर्देश दिए कि एकल पीठ ने कहा कि प्रदेश के सभी 75 जिलों में आरम्भ एफए और उमर 25 जूई निम्नां का सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है। अदालत ने कहा कि हथियार लाइसेंस जारी करने, नवीनीकरण और ट्रांसफर को प्रक्रिया में भारी



इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से मांगी जवाब

लापरवाही बरती जा रही है। इस दौरान हाईकोर्ट के सामने राज्य सरकार की ओर से दाखिल हलफनामा में चौकाने वाले आंकड़े सामने आए। प्रदेश में अब तक 10 लाख 8 हजार 953 हथियार लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं, साथ ही 23 हजार 407 आवेदन अभी भी लंबित हैं। एक हजार 738 अवेरत कामिश्नरों के पास लंबित हैं। 6 हजार 62 ऐसे लोगों के लाइसेंस दिए गए हैं, जिन पर दंड था। उससे ज्यादा आपाधिक मुकदमें दर्ज हैं। अदालत ने इस पर नाराजगी जताते हुए पूछा कि आखिर ऐसे लोगों को हथियार लाइसेंस

किस आधार पर दिए गए? हाईकोर्ट ने कहा कि हथियारों का सांख्यिक प्रदर्शन समाज में डर और असुरक्षा का माहौल पैदा करता है। अदालत ने साफ कहा कि आपत्तिका के नाम पर 'गन कल्चर' को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। कोर्ट के मुताबिक हथियारों का खुलेआम प्रदर्शन समाजिक अस्थिरता पैदा करता है और कानून व्यवस्था पर लाल अडान होता है। जिन लोगों को डिटेन मांगा गई है, वो हैं रघुचंद्र प्रताप सिंह (राजा भैया), धनंजय सिंह, दुर्गा सिंह, अजय मखर, सुशील सिंह, इंदर सिंह, सुनील यादव, फरार सिंह, बाराहा सिंह, संगम सिंह, सुलोक सिंह, चूल, युल सिंह, सनी सिंह, हनु सिंह और डा. उदय नाथ सिंह।

अगली सुनवाई 26 मई को होगी, सरकार देगी जवाब

अदालत ने सुनवाई 26 मई को होगी वाली आगामी सुनवाई पर टिप्पणी की, जहां सरकार और पुलिस प्रशासन को विस्तृत जवाब देना होगा।

पूर्वी यूपी में गर्मी लेगी और विकराल रूप

शाह टाइम्स ब्यूरो



अगले 48 घंटे के दौरान तापमान में दो से तीन डिग्री तक की बढ़ोतरी होने के आसार

लखनऊ। प्रचंड गर्मी और तीव्र ताप लहर का सामना कर रहे उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में अगले 48 घंटे के दौरान तापमान में दो से तीन डिग्री तक की बढ़ोतरी होने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई जिलों में शुक्रवार को भी उष्ण लहर से लेकर भीषण उष्ण लहर चलने की संभावना है। अगले 48 घंटों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में तापमान में दो से तीन डिग्री सिलसियस तक की और बढ़ोतरी होने के आसार हैं। विभाग द्वारा जारी उष्ण लहर बुलेटिन के अनुसार बीते 24 घंटों में प्रयागराज, सुलतानपुर और गाजीपुर का अधिकतम तापमान सामान्य से काफी अधिक दर्ज किया गया, जबकि लखनऊ, बाराणसी, कानपुर नगर, बाराणसी, बहराच, बांदा, मुजफ्फरनगर और मेरठ समेत कई

जिलों में तापमान सामान्य से ऊपर रहा। बांते दिन बाराणसी (बीएचएच), प्रयागराज, बांदा, सुलतानपुर, गाजीपुर, उरई, हमीरपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ में लू और भीषण लू को स्थिति दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को बांदा, चित्रकूट, कोशी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रयागढ़, मिर्जापुर, बाराणसी, संत रविदास नगर और जौनपुर जिलों में भीमण लू चलने की आशंका है। वहीं सोमपूर, चंडौली, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली, अमठी, सुलतानपुर, मेरठ, गोरखपुर, आगरा, झांसी और लखनऊ में भारी चले सकने हैं। विभाग ने बताया, बहराच और गोरखपुर में होट इंडेक्स 50 से 60 डिग्री सिलसियस के बीच रहने की संभावना जाड़ी है, जबकि मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मिर्जापुर, सोनभद्र और रायबरेली समेत कई जिलों में यह 40 से 50 डिग्री सिलसियस के बीच रह सकता है। मौसम विभाग ने लोगों को दोषाहर 11 बजे से तीन बजे तक धूप में निकलने से बचने, पानी पीना में पानी और ठंडा पदार्थ लेने तथा हल्के सूती कपड़े पहनने को सलाह दी है। विभाग ने जखदुर, बुधुगौ, बच्चा और गांधी बोमार्गियों से प्रसित लोगों को विशेष सावधानी बरतने को कहा है।

बिजली संकट से निजात दिलाने में कदम उठाए सरकार

शाह टाइम्स ब्यूरो



बसपा प्रमुख भायावती ने भी कांग्रे

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष भायावती ने उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती पर चिंता जताते हुए कहा कि सरकार को बिजली संकट से आमजन को निजात दिलाने के लक्षित उपाय करने चाहिए।

अति-कठपंती बचा हुआ है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर लोग विचिन्न क्यों में अपना आक्रोश भी प्रकट कर रहे हैं। बिजली चला सार्वभौमिक अधिकार है। बिजली का जीवन निरंतर रहती है। सरकार से अपील है कि वह बिजली आपूर्ति में बाधाओं को दूर करे। मुसमंजरी को दूर करने के लिए बिजली आपूर्ति में बाधाओं को दूर करने का प्रयास करें ता वह व्यापक जनहित में उचित होगा।

पहले उत्तर प्रदेश की पहचान गुंडाराज और माफिया राज से होती थी: सीएम योगी

विकसित राज्य के रूप में पहचान बना रहा यूपी

देवरिया, बार्ता



देवरिया के पोखरभंडा गांव में आयोजित जनसभा में बोले सीएम योगी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश को पहचान 'एक खिला एक उन्पार', सुरक्षा, कानून के राज और तेजी से विकसित हो रहे राज्य के रूप में बन रही है। अगले पहले प्रदेश को पहचान गुंडाराज और माफिया राज से होती थी।

योगी शुक्रवार को देवरिया शहर से धर्मिक पोखरभंडा गांव में आयोजित जनसभा में संबोधित कर रहे थे। 45 हजार उद्योग 655 करोड़ 45 लाख रुपए लागत की 19 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि देवरिया की जनता में भाजपा को जिले की सारी विधासभा सदस्यों को विजय दिलाई

देवरिया के

पोखरभंडा गांव में आयोजित जनसभा में बोले सीएम योगी राज्य में अब कानून व्यवस्था बेहतर

एक वोट की ताकत से अयोग्यता में भ्रष्टाचार का मूक चरम नहीं माना, जबकि, कारी, विधवावसिनी धाम और बुढ़ावन से धर्मिक स्थल अपनी सांस्कृतिक विरासत और पहचान के साथ विकसित हो रहे हैं। योगी ने कहा कि आज प्रदेश में महिला, बेटियां और व्यापारी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं से छेड़छाड़ करने वालों के लिए अगले चारोंह पर यमराज इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा

सबकी समस्या का समाधान सरकार

की प्रार्थनाकता: मुख्यमंत्री

गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान शुक्रवार सुबह गोरखपुर मॉरिंग में आयोजित जनसभा में आगे लोगों को आश्वासन करते हुए कहा कि सबकी समस्या का समाधान सरकार की प्रार्थनाकता है। गोरखपुर मॉरिंग के महं दिवसव्यवस्था स्मृति पत्र के बाहर आयोजित जनसदन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 150 लोगों से मुलाकात कर जनसमस्याएं सुनी और लोक पर मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसमस्याओं का निस्तारण तुरन्त, परिश्रति और सर्वेसर्वालीय ढंग से किया जाए। इसमें किसी भी तरह की शिथिलता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। जनसमस्या का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण और सर्वेसर्वालीय ढंग से किया जाए। उन्होंने सबके प्रार्थना पत्र को संबोधित अधिकारियों को संदर्भित करते हुए शीघ्रता से समस्या समाधान के लिए निर्देशित किया।

कि वर्ष 2014 के बाद उत्तर प्रदेश की छवि में व्यापक बदलाव आया है। अत्यागर, प्रदाचार और अज्ञान, कला से बाहर निकलकर स्तर पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बढ़ाई है।

सेक्टर 75415.35
फ्लिपटी 23719.30



बिज़नेस-टाइम्स

टोलो 159490 प्रति 10 बाला
चांदी 285000 प्रति किलो

निजी क्षेत्र के बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के शेयरों को निवेशकों का समर्थन

मुंबई, बार्ता

निजी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय सेवा कंपनियों के शेयरों को निवेशकों के समर्थन तथा इंडीविजुअल और अवसरचना क्षेत्र से जुड़ी कुछ चुनिंदा कंपनियों के शेयरों में लिवाली निकलने से स्थानीय शेयर बाजार में प्रमुख शेयर सूचकांक शुक्रवार को बहुत से साधकों बंद हुए। शुक्रआती कारोबार में सूर्य को निमनयन में सुधार के संकेतों से भी बाजार को समर्थन मिला।

बंदो बाजार का संवेकस 231.99 अंक या 0.31 फीसदी बढ़कर 75,415.35 पर बंद हुआ, जबकि निचरी 64.60 अंक या 0.27 प्रतिशत बढ़कर 23,719.30 पर बंद हुआ। संवेकस सुबह 75,260.39 पर खुलने के बाद ऊपर में 75,810.97 और नीचे में 75,230.75 अंक तक गया। कुल बाजार 75,183.36 पर बंद हुआ था। इसी तरह निचरी 50 सुबह 23,671.20 पर खुल कर ऊपर में 23,835.65 और नीचे में 23,671.20 तक गया। बीएसई 100 में बाजार को समर्थन के आखिरी 15 शेयर

सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट

नई दिल्ली, बार्ता

सोने और चांदी की कीमत में शुक्रवार को शुरूआती कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। एसीएसएन पर सोना करीब 700 रुपए गिरा हुआ है, जबकि चांदी की कीमत में 1,600 रुपए की गिरावट आई है। परिणाम परिणाम में ताम्रबंद बने से कच्चे तेल को बाजार बंदी है और साथ ही डॉलर रूडेंस भी मजबूत हुआ है। इससे फेडरल रिजर्व सोने में बढ़ोतरी कर सकता है। इसका असर सोने और चांदी की कीमत पर देखने को मिल रहा है। गूड रिटर्नस के मुताबिक 24 कैरट वाला सोना 440 रुपए की गिरावट के साथ 1,59,490 रुपए पर आ गया। 18 कैरट वाले सोने को कीमत 330 रुपए गिरकर 1,19,620 रुपए रह गई। चांदी 2,85,000 रुपए प्रति किलो के भाव पर टूट कर रही है। बीते सत्र में बाजार बंद होने के बाद राष्ट्रीय राबधानी में चांदी की कीमत 5,000 रुपए उछली।

भारत-साइप्रस में हुए छह समझौते

नई दिल्ली, बार्ता

भारत और साइप्रस ने द्विपक्षीय संबंधों को प्राथमिकता साझेदारी के स्तर तक उन्नत करने के साथ-साथ रक्षा, आतंकवाद-रोधी सहयोग, साइबर सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और समुद्री सहयोग समेत छह समझौतों पर हस्ताक्षर किए और संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में आठ घोषणाएं कीं।

भारत को तीता दिन की यात्रा पर आये साइप्रस के राष्ट्रपति महामहिम निकोस आंसोइल्लासुस के साथ शुक्रवार को यहां प्रथममंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय बार्ता के बाद इन समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच जिन छह समझौतों सांझा पर हस्ताक्षर किए गए उनमें आतंकवाद-रोधी संयुक्त कार्य समूह की स्थापना, 2026-2031 के लिए रक्षा सहयोग रूडेंस, साइबर सुरक्षा सहयोग, नवाचार और डिजिटल नीति उद्यम सहित तथा भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं

प्रथम पृष्ठ के शेष...

दुनिया की... है। कर्ल, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, कर्नाटक और तमिलनाडु में मोदी बार्ता हो सकती है। अंध्र प्रदेश, कर्नाटक और झारखंड में 50-60 किमी प्रति घंटे की स्तर पर औपेी-पुनर्गण को बेतकनी दी गई है। उत्तर प्रदेश के बॉपर, बिजकूट, ओशीनी, प्रयागराज इलाका में हीरोइन का रूड अडर है। राज्य का बांदा गुरवार को लखनऊ से दिव देना का सबसे बड़ा शहर रहा। यहां तापमान 47.6 डिग्री सिलसियस तक पहुंचा। उसके अलावा प्रयागराज में 46.6 डिग्री सिलसियस तापमान में 45.6 डिग्री सिलसियस, हमीरपुर और सुलतानपुर में 45.2 डिग्री सिलसियस तापमान रहा। हरियाणा में गंग रात का 38 साल का रिकार्ड टूटा। गुरवार का पिचानी में रात का तापमान 36.6 डिग्री सिलसियस था, जो साल 1988 में 34.8 डिग्री सिलसियस रहा था। उत्तर प्रदेश का हरियाणा का हरियाणा नवंबर शहर रहा, बांदा अधिकतम तापमान 45.8 डिग्री सिलसियस रहा। उग्रावटूड 6 जिलों में हीरोइन के आतं, महर्गो समेत हिल स्टेशन में पाया 30 डिग्री सिलसियस पर, नैनीताल में स्कूलों का समय बदला उग्रावटूड के 6 जिलों में आज हीरोइन और 5 जिलों में बंसाधन का अडर है। मुरी, नैनीताल और लखनऊ जैसे

हिल स्टेशनों में भी अधिकतम तापमान 30 डिग्री सिलसियस के ज्यादा पहुंच रहा। शुक्रवार को नैनीताल में स्कूलों का समय बदला गया। री पंचांग सरकार ने गर्मी को बजह से सरकारी पंचांग और स्कूलों का समय बदल दिया है। अब दूधर और स्कूल सुबह साढ़े 7 बजे खुलने और दोपहर 1.30 बजे बंद होगी। स्कूलों के अंतरा सभी कलासंब के लिए होंगे। यह आदेश सोमवार यानी 25 मई से लागू होंगे। प्रथम महान्त में नया कहा कि भीषण गर्मी को रोकते हुए फैसला लिया है।

शिक्षा मंत्री धर्मचं... थे। अधिबन्त के इस कदम के बारे में अन्कर हमारी रातों की नींद उड़ गई है। भगवान दोषके ने कहा कि आज का माहौल देखकर डर लगाना व्यापारिक है। यहां उससे किन्ने भी उल्लोखनीय नहीं है। उमरने खुद भी भारत आने पर विचारण करने का डर जाहिर किया है। यह मधुपुर हो गया है, और ऐसे लोगों को अक्षर विचारण कर लिया जाता है। विचित्री रो रातों से में इसी स्थिति में सो नहीं पाया है कि उरके साक्षात् का सकता है। अधिबन्त को भी नया कि इसमें कौनकोर पाटी के बां में अनेके उरके पाटी के सा चलता था। मैं चाहती हूँ उरके जवाबिती से दूर रहूँ। आप' के साथ काया कर चुका था। उरक समय भी मैंने उरके काया था कि हमारा रजनीति से कोई लेना-देना नहीं है और उरके कोई-नकीर कर लेनी चाहिए।

विकसित हुई किफायती और उच्च-प्रदर्शन वाली थर्मल बेटर्री सामग्री

नई दिल्ली, बार्ता

भारतीय वैज्ञानिकों ने ऐसी किफायती तथा उच्च-प्रदर्शन वाली थापीय ऊर्जा भंडारण सामग्री विकसित की है जो कि, द्वि-तरा ऊर्जा (सौरपीसी) संयंत्रों और औद्योगिक अपशिष्ट ऊष्मा पुनर्प्राप्ति प्रणालियों में उपयोग होने वाली बेटर्रीयों की क्षमता को काफी बढ़ा सकती है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डीएचटी) के स्वयंसेवा इंडस्ट्रियल एडवांस्ड रिसर्च डेवेलपमेंट फाउंडर मेंगवली एंजि उच्च-प्रदर्शन थर्मल बेटर्रीयों के शोधकर्ताओं ने थर्मल ऊर्जा भंडारण अनुप्रयोगों के लिए सिमनेने नैनी कर्नाटक फंज चर्च मेंटरीयल (पीओपीए) विकसित करने की एक लक्षण प्रभावों को बड़े पैमाने पर अग्रगण्य का प्रकलन वाली प्रक्रिया तैयार की है। उन्होंने कहा कि शोध के दौरान वैज्ञानिकों ने माया कि फंज चर्च मेंटरीयल में केवल एक प्रतिशत रिप्लस अक्साइड नैनीकम मिलाने से उसकी विशिष्ट उष्मा क्षमता में करीब 45 प्रतिशत तक वृद्धि हो गई। विशिष्ट उष्मा क्षमता किफायती परधों की ऊष्माय ऊर्जा संग्रहित करने की क्षमता को दर्शाती है। नैनीकण के बेहतर फैसले से सामग्री की स्तर ऊर्जा बढ़ती है।

नीट पेपर लीक की जिम्मेदारी लें मोदी व प्रधान

परीक्षा के पेपर लीक मामले में सरकार ने संसदीय समिति के समक्ष गलत बयान दिया

नई दिल्ली, बार्ता

कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि नीट-यूपी 2026 परीक्षा के पेपर लीक मामले में सरकार ने संसदीय समिति के समक्ष गलत बयान दिया है और 2024 के पेपर लीक की सच्चाई छिपाने का प्रयास किया है, जिससे लाखों छात्रों का नुकसान हुआ है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा शिक्षा मंत्री धर्मचंद्र प्रयाग को इसकी जिम्मेदारी लीनी चाहिए।

सरकार ने यह भी आरोप लगाया है कि मोदी पार्टी के नेताओं ने नीट-यूपी (एनटीए) के मामले में परीक्षा धोखेबाजी और पेपर लीक मामले को सचवाई दबाने का काम कर रही है तथा नीट-यूपी 2026 परीक्षा में पेपर लीक मामले को सचवाई दबाने का काम कर रही है। कांग्रेस संघर्ष विभाग के प्रभारी जयराज मालते को नरकाने की कोशिश शामिल है। उन्होंने कहा कि नीट-यूपी 2026 परीक्षा में पेपर लीक मामले को सचवाई दबाने का काम कर रही है। कांग्रेस संघर्ष विभाग के प्रभारी जयराज मालते को नरकाने की कोशिश क्यं कर रही है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार इससे पहले भी नीट-यूपी 2024 में सामने आई व्यवस्था अनियमितताओं को दबाने की कोशिश कर चुकी है।

धांधलियों को छिपाने में जुटा है एनटीए: कांग्रेस

नई दिल्ली, बार्ता

कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ने प्रतिगोणी परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने के लिए जिन राशियां परीक्षा परीक्षा (एनटीए) का गठन किया था, वह परीक्षा धोखेबाजी तथा अनियमितताओं को सचवाई छिपाने का काम में जुटा है। अब नीट-यूपी 2026 परीक्षा में कथित पेपर लीक मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस संघर्ष विभाग के प्रभारी जयराज मालते ने शुक्रवार को सांख्यिकी विभाग 'एक्स' पर कहा कि 2018 में एनटीए के गठन के बाद से ही सरकार और उसका तंत्र परीक्षा माफिया के साथ मिलीभगत कर एनटीए द्वारा आयोजित परीक्षाओं में व्यापक अनियमितताओं और धांधली को सचवाई दबाने में लागू हुआ है। उन्होंने कहा कि एनटीए को बहाल करे हुए एक कि एनटीए के मानकनिश्चय के एक संसदीय समिति के समक्ष दावा किया कि नीट-यूपी 2026 को पेपर लीक नहीं हुआ।

काम कोर्स
उत्तम क्यों?
अधिक संख्या में इंग्लिश, हिस्ट्री, गणित, रसायन, जीवशास्त्र, गुरुकुल, गुरुकुल, बाराणसी की शैक्षणिक से इमेरा के लिए चुनकार।
फोन कर रहे औरिषियों डाक द्वारा प्राप्त करें।
नृपति इंटरनेशनल
08899787114
09808917010

दशमी
देवास्थानी
997161320, 8272800800

Cipzer
जॉइन्डिस क्योर
लिवर का जगिरो पीएल
यूपी की सभी सरकारी ऑफिस, बैंक और एनटीए के सभी परीक्षा में शामिल होने के लिए
आप को दिए हुए एड्रेस पर भेजिए।
86 8484 5757 info@cipzer.com



चर्चाओं में अभिजीत

एक्स पर बैन के बावजूद कांक्रोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके चुप होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। शक्रवार को सोशल मीडिया पेज बनाने के सात दिन बाद वह पहली ऑनलाइन पिटीशन लेकर आए हैं। इस पॉजिशन में उन्होंने नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। इस पिटीशन में लोगों से विशेषकर युवाओं से साइन करने के लिए कह रहे हैं। ताकि सिस्टम की गलती पर सवाल उठ सकें। ऐसा कम ही होता है कि कोई व्यक्ति कुछ ही दिनों में जीरो से हीरो बनने की तरफ अपना सफर तय करे। जिस तरह अभिजीत दीपके को इस आइडिया पर फॉलोवर्स जुड़े हैं वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। इतने फॉलोवर्स तो भाजपा व कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय राजनीति में स्थापित पार्टियों के पास भी नहीं हैं। फॉलोवर्स का यह आंकड़ा मात्र छह दिन में ही दो करोड़ के पास पहुंच गया है और यह सिलसिला बराबर जारी है। यहीं इस तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। अभिजीत दीपके के माता-पिता अपने पुत्र को लोकप्रियता से सहम भी दिखाई दे रहे हैं और अपने बयान में अपने पुत्र को यह नसीहत देते दिखाई दे रहे हैं कि उनको राजनीति से दूर ही रहना चाहिए। उनके माता-पिता को डर है कि कहीं उनका बेटा किसी मुसीबत में पड़ जाए। अभिजीत दीपके के पिता भगवान ने एक मराठी न्यूज चैनल को बताया कि वह अपने बेटे को राजनीति में नहीं भेजना चाहते थे। उसकी प्रसिद्धि से हमारी रातों की नींद उड़ी हुई है। भगवान ने साफ कहा कि आज का माहौल देखकर डर लगना स्वाभाविक है, अपने इंटरव्यू में वह यह कहते दिखाई दे रहे हैं कि चाहे उनके पुत्र के कितने भी फॉलोवर्स क्यों न हों। अभिजीत ने खुद भी भारत लौटने पर गिरफ्तार होने का डर जाहिर किया है। उनकी माता के भी ऐसे ही विचार हैं वह नहीं चाहती कि उनका पुत्र राजनीति में आए और किसी पचड़े में पड़े। माता के अनुसार उनका राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है और वह चाहती हैं कि उनका पुत्र कोई नौकरी कर ले। अब सवाल यह है कि अभिजीत के माता-पिता के डर को किस रूप में लिया जाए। आखिर एक लोकतांत्रिक देश में डरने की वजह क्या हो सकती है। लोकतांत्रिक देश का मतलब ही यह होता है कि जहाँ लोग खुलकर अपनी राय रख सकें, चाहे कोई इससे सहमत हो या असहमत। अभिव्यक्ति पहली प्राथमिकता होती है, लेकिन उसके माता-पिता का डर बता रहा है कि भले ही चाहे हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, लेकिन खुलकर अपनी आवाज को उठाना अभी भी इतना आसान नहीं है। विशेषकर सरकार को लेकर। इस तरह का वातावरण नहीं होना चाहिए और इस पर सरकार को भी गंभीरता से विचार करना चाहिए कि उसके क्रियाकलापों से देश के भीतर किस तरह का संदेश जा रहा है।

काला सोना या देश का हरा भविष्य?

ऊर्जा और विकास की जटिल धारा में बहता सिंगरौली आज फिर सुर्खियों के शिखर पर है। यह वही क्षेत्र है जहाँ कोयले की परतों के नीचे आर्थिक आकांक्षाएँ और पर्यावरणीय प्रश्न साथ-साथ साँस लेते हैं। 21 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने अजय दुबे की याचिका विलंब के आधार पर खारिज की, जिसमें अडानी समूह की महान एनर्जन लिमिटेड (धीरौली कोल ब्लॉक) की वन/पर्यावरण मंजूरी को चुनौती दी गई थी। यह आदेश केवल न्यायिक प्रक्रिया की औपचारिकता नहीं, बल्कि विकास की रफ्तार और नीति-स्थिरता को नई दिशा देने वाला संकेत भी है। कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध यह इलाका अब एक बार फिर राष्ट्रीय ऊर्जा विमर्श के केंद्र में मजबूती से उभर आया है, जहाँ भविष्य की राह अब अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगी है।

कानूनी अनिश्चितता की परत हटते ही परियोजना के लिए स्थिरता का नया आधार तैयार हो गया है, जो बड़े निवेश और खनन गतिविधियों को गति देता है। सुप्रीम कोर्ट ने समयबद्ध न्याय व्यवस्था का महत्व स्पष्ट करते हुए कहा कि देरी से दाखिल याचिकाएँ विकास की प्रक्रिया को बाधित नहीं कर सकतीं। इसी संदर्भ में सिंगरौली की यह परियोजना राष्ट्रीय ऊर्जा ढाँचे में एक मजबूत कड़ी बनती दिखाई दे रही है। बढ़ती ऊर्जा जरूरतों के बीच यह निर्णय वर्तमान माँगों को संभालते हुए भविष्य की दिशा भी निर्धारित करता है। यह फंसला न्याय और विकास के बीच संतुलन का सशक्त उपहार है। ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में यह परियोजना एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। धीरौली कोल ब्लॉक की अधिकतम उत्पादन क्षमता 6.5



मिलियन टन प्रति वर्ष (6.5 एमटीपीए) निर्धारित है, जिसमें मुख्य रूप से ओपन-कास्ट खनन शामिल है। इस कोयला उत्पादन से अडानी पावर की बिजली उत्पादन श्रृंखला मजबूत होने की उम्मीद है। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और ऊर्जा की बढ़ती माँग को देखते हुए यह परियोजना बिजली आपूर्ति को स्थिर बनाए रखने, उत्पादन लागत को नियंत्रित करने और औद्योगिक विकास को गति देने में सहायक सिद्ध हो सकती है। आधुनिक खनन प्रौद्योगिकी के उपयोग से न केवल उत्पादकता बढ़ेगी बल्कि ऊर्जा क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता को भी मजबूती मिलेगी।

इस परियोजना से मध्य प्रदेश में आर्थिक संभावनाओं का विस्तार होने की संभावना है। स्थानीय स्तर पर हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे, जिससे सिंगरौली और आसपास के क्षेत्रों में बेरोजगारी दर कम करने में मदद मिलेगी। छोटे-मध्यम उद्योगों, ट्रांसपोर्ट, होटल, दुकानों और सेवा क्षेत्र को नई गति मिलने की उम्मीद है। राज्य सरकार को रॉयल्टी, टैक्स

और अन्य मदों से पर्याप्त राजस्व प्राप्त होगा। साथ ही सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास को भी गति मिलेगी। विकास की दौड़ जितनी तेज हो रही है, पर्यावरणीय चेतावनी उतनी ही स्पष्ट और गंभीर स्वर में सामने खड़ी है। सिंगरौली की धरती पहले से ही कोयला खनन के दबाव तले संतुलन बनाए रखने की कोशिश करती रही है। वन भूमि का घटता दायरा, वृक्षों की कटाई और जैव विविधता पर बढ़ता संकट अब अनदेखा नहीं किया जा सकता। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आधुनिक तकनीकों जैसे धूल नियंत्रण प्रणाली, जल पुनर्चक्रण और उन्नत प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का प्रभावी उपयोग किया जाए, तो पर्यावरणीय क्षति को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसके साथ ही अनिवार्य वनरोपण, मिट्टी संरक्षण और जल स्रोतों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देना आवश्यक है। किसी भी बड़े विकास की असली कसौटी उसकी सामाजिक स्वीकार्यता और स्थानीय भागीदारी होती है। यह परियोजना भी



केवल आर्थिक या तकनीकी सफलता पर नहीं, बल्कि समुदायों के समावेशन पर निर्भर करेगी। प्रभावित क्षेत्रों के हजारों परिवारों के लिए पुनर्वास और उचित मुआवजा जरूरी है। वन अधिकार अधिनियम के तहत सभी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए उनकी आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। कौशल विकास के जरिए स्थानीय युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करना और उन्हें प्राथमिकता देना भी आवश्यक है।

जब समुदाय विकास का हिस्सा बनेगा, तभी यह परियोजना वास्तव में टिकाऊ और स्वीकार्य होगी। न्यायिक निर्णयों की दिशा में यह फैसला एक स्पष्ट संदेश छोड़ता है कि प्रक्रिया में अनावश्यक देरी विकास की गति को रोक नहीं सकती। याचिका के आधार पर खारिज करना इस बात का संकेत है कि बड़े प्रोजेक्ट लंबे मार्गदर्शक बनकर उभर रहा है। साथ ही यह भी अपेक्षित है कि विकास कार्य पर्यावरणीय मानकों और सामाजिक दायित्वों का सख्ती से पालन करें। कानून का वास्तविक उद्देश्य अनुभूति के साथ-साथ संतुलन स्थापित करना भी है। सतत विकास आज विकास की दिशा तय करने वाला सबसे निर्णायक सिद्धांत बन चुका है।

श्रीमुख से...

मेहनतकशों का जीवन अति कष्टदायी बना

सरकार को बिजली संकट से आमजन को निजात दिलाने के त्वरित उपाय करने चाहिए, बिजली संकट से गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, छोटे व्यापारी और करोड़ों मेहनतकश लोगों का जीवन अति-कष्टदायी बन गया है, उत्तर प्रदेश जैसे विशाल आबादी वाले राज्य में भीषण गर्मी के इस मौसम में बिजली की कम आपूर्ति व कटौती आदि की आम शिकायतों को लेकर लोग विभिन्न रूपों में अपना आक्रोश भी प्रकट कर रहे हैं, जिसकी चर्चा समाचार माध्यमों में भी काफी व निरन्तर रहती है, सरकार बिजली आपूर्ति सम्बंधी लोगों के कष्ट व परेशानियों को ध्यान में रखते हुए जरूरी उपाय तत्काल सुनिश्चित करे, साथ ही, नए बिजलीघर के माध्यम से भी आगे के लिए बिजली आपूर्ति को सुधारने का प्रयास करे तो यह व्यापक जनहित में उचित होगा।



—श्री मायावती, अध्यक्ष, बसपा

अपने विचार रखें...

हम पाठकों के साथ ही वरिष्ठ स्तंभकारों, लेखकों को सम्पादकीय पेज हेतु आलेख अथवा जनमानस से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय भेजने के लिए आमंत्रित करते हैं, सम्पादकीय पेज पर प्रकाशित किसी भी लेख से सम्पादक अथवा संस्थान का सहमत होना आवश्यक नहीं है, यह लेखक के अपने निजी विचार होते हैं।

सम्पादकीय डेस्क

पत्राचार: सुजड़ चुंगी, मेरठ रोड मुजफ्फरनगर, पिन कोड-251003
Dainikshahtimes@gmail.com

खरीफ सीजन से पहले उर्वरक संकट बढ़ा



खरीफ सीजन के नजदीक आते ही देशभर में उर्वरकों की उपलब्धता को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। कई राज्यों के किसान धान, मक्का, कपास और गन्ने जैसी फसलों के लिए आवश्यक उर्वरकों की समय पर आपूर्ति को लेकर परेशान हैं। भारत में कृषि करोड़ों लोगों की आजीविका का आधार है, इसलिए उर्वरकों की कमी सीधे फसल उत्पादन और खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करती है। भारत दुनिया में उर्वरकों का सबसे बड़ा उपभोक्ता देशों में से एक है। देश में यूरिया का उत्पादन बड़े स्तर पर होता है, लेकिन मांग

को पूरा करने के लिए अब भी काफी मात्रा में आयात करना पड़ता है। वहीं पोटाश की बात करें तो भारत लगभग 90 प्रतिशत पोटाश विदेशों से आयात करता है। यह अधिक आयात निर्भरता भारतीय कृषि को वैश्विक कोमलों, आपूर्ति संकट और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों पर निर्भर बना देती है। पिछले कुछ वर्षों में ईंधन और परिवहन लागत बढ़ने के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। सरकार किसानों को 45 किलो यूरिया की बोरी लगभग ७70 की सब्सिडी दर पर उपलब्ध कराती है, लेकिन कमी के समय कई किसानों को यही बोरी काले बाजार में ७400 से

७700 तक में खरीदनी पड़ती है। इसका सबसे अधिक असर छोटे और सीमांत किसानों पर पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार उर्वरकों में आयात निर्भरता कम करने और नैनो यूरिया, जैविक खाद तथा संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने की बात कर चुके हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भारत उर्वरकों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाए और टिकाऊ कृषि प्रवृत्तियों को अपनाए, तो यह कृषि

क्षेत्र के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। यदि हम अभी से सही कदम उठाते हैं, तो इसका लाभ केवल खरीफ ही नहीं बल्कि रबी सीजन की फसलों को भी मिलेगा। इससे किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध होंगे, खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी और भारतीय कृषि अधिक आत्मनिर्भर बन सकेगी।

—शाशी रोहिल्ला, अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर

व्या है भारत में विद्या व विद्यार्थियों का भविष्य

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारा देश से जो जा रही रश्मन की बात 131 वें एपिसोड में गत 22 फरवरी 2026 को छात्रों से रश्मिना पे चर्चा की थी। अपने इस संवाद कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने छात्रों को दिए गए १३ उपायों में कहा कि धर्मों से किसी की योग्यता तय नहीं होती। शिक्षा जीवन को संभालने का एक माध्यम है, जबकि परीक्षा केवल आत्म-मूल्यांकन का जरिया है। उन्होंने छात्रों से परीक्षा को किसी बड़े बोझ या हॉबे के रूप में देखने के बजाय इसे एक उत्सव की तरह मनाने की अपील की थी। पढ़ाई, आराम, शारीरिक खेलकूद और अपने शौक के बीच एक सही संतुलन बनाने को जरूरी बताया था। मोदी ने छात्रों को सलाह दी थी कि कुछ छात्र रात में पढ़ना पसंद करते हैं तो कुछ सुबह जल्दी, अपनी इसी मूल शैली पर विश्वास रखें। उन्होंने छात्रों को यह सलाह भी दी कि वे अपने मन की चिंताओं को अपने माता-पिता और परिवार के साथ खुलकर साझा करें, जिससे मानसिक तनाव कम होता है। अधिभावकों को सलाह देते हुए उन्होंने कहा था कि माता-पिता को बच्चों पर उनकी इच्छा के विरुद्ध विधि-विधान करियर चुनने का दबाव नहीं बनाना चाहिए। हर बच्चा अपने आप में अलग होता है। इसी तरह उन्होंने शिक्षकों को भी सलाह दी कि उन्हें छात्रों की सीखने की गति को समझना चाहिए और उनके लिए ऐसे लक्ष्य तय करने चाहिए जो पहुंच में हों लेकिन जिन्हें प्राप्त करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़े। प्रधानमंत्री के उपरोक्त कथन में यह बात पूरी तरह विरोधाभासी है कि धर्मों से किसी की योग्यता तय नहीं होती। क्योंकि आज के दौर में एडमिशन, वरीयता सूची, श्रेणी निर्धारण आदि हर जगह अंक प्रतिशत की ही होड़ लगी हुई है। परन्तु पीएम ने इन्होंने छात्रों को कभी यह नहीं बताया कि यदि आपकी जी तोड़ मेहनतों के बाद परीक्षा के पंचे लीक हो जाएं व परीक्षा ही स्थगित कर दी जाए तो आखिर छात्रों को ऐसे सदमे से कैसे उबरना चाहिए।

—निर्मल रानी

गन्ना अधिनियम 2026 पर टिप्पणी एवं सुझाव

भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित गन्ना अधिनियम 2026 का उद्देश्य चीनी उद्योग, एथेनॉल उत्पादन तथा किसानों के भुगतान तंत्र को आधुनिक बनाना है। यह अधिनियम पुराने कानूनों में सुधार कर नई तकनीक और उद्योग की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार व्यवस्था बनाने का प्रयास है हालांकि इस अधिनियम में शुगर रिकवरी आधारित मूल्य निर्धारण का प्रावधान किसानों के हित में पूर्ण रूप से उचित नहीं माना जा सकता। वर्तमान समय में गन्ना केवल चीनी उत्पादन का स्रोत नहीं रह गया है बल्कि इससे एथेनॉल, बिजली उत्पादन, पेपर उद्योग के लिए अवशेष, बायो फ्यूल तथा अन्य कई बायो प्रोडक्ट भी तैयार किए जाते हैं।

यदि किसी गन्ने में शुगर रिकवरी कम होती है तो उसमें अवशेष एवं अन्य पदार्थ अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं। जिनका औद्योगिक उपयोग और आर्थिक मूल्य भी महत्वपूर्ण होता है। इसलिए केवल शुगर रिकवरी के आधार पर किसानों को मूल्य देना उचित नहीं है। यदि रिकवरी आधारित कानून लागू करना आवश्यक हो तो गन्ने से बनने वाले सभी उत्पादों और



सुबोध कुमार राजपुर

उनके आर्थिक मूल्य को भी गणना में शामिल किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त गन्ने में चीनी की रिकवरी बढ़ाने में पोटाश एवं मैग्नीशियम की सीधी और महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह भी समझना आवश्यक है कि लगभग 1000 क्विंटल प्रति हेक्टेयर गन्ना उत्पादन लेने पर फसल मिट्टी से लगभग 250 किलोग्राम पोटाश ग्रहण करती है। यदि इस 250 किलोग्राम पोटाश की कीमत बाजार में उपलब्ध मोप के आधार पर गणना की जाए तो इसकी लागत लगभग 8750 रुपये या उससे अधिक बैठती है अर्थात् किसानों की भूमि में मौजूद पोषक तत्वों का उपयोग चीनी मिल मालिकों एवं उद्योगों द्वारा वर्षों से किया जाता रहा है लेकिन किसानों को उसका वास्तविक मूल्य कभी नहीं दिया गया। जब मिट्टी में पुनः पोषक तत्व डालने और

उर्वरकों पर खर्च करने की बारी आती है तब रिकवरी आधारित भुगतान की बात की जाती है। यह व्यवस्था किसानों के साथ न्यायसंगत नहीं कही जा सकती। बायो प्रोडक्ट उद्योग तेजी से विकसित हो रहा है। नई तकनीकों और उपयोगों के कारण गन्ने का औद्योगिक महत्व हर वर्ष बढ़ रहा है। इसलिए एक कानून स्थाई रूप से न बनाकर प्रत्येक 10 वर्ष बाद पुनः समीक्षा और संशोधन के साथ लागू किया जाना चाहिए। रिकवरी आधारित मूल्य निर्धारण किसानों के शोषण का कारण बन सकता है। वर्तमान व्यवस्था में कई मामलों में यह निर्णय उद्योगों और बाजार की आवश्यकता के अनुसार चलता है। यदि रिकवरी वास्तव में उद्योग के लिए हानिकारक होती तो देश में चीनी मिलों की संख्या लगातार ना बढ़ती और नई मिलें स्थापित करने की योजनाएं न बनती। अतः गन्ना अधिनियम 2026 बनाते समय किसानों के हितों की रक्षा, गन्ने से बनने वाले सभी उत्पादों का आर्थिक मूल्यांकन, मिट्टी की उर्वरता की वास्तविक लागत



तथा उद्योग और किसानों के बीच संतुलित व्यवस्था को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।



अमेरिका ने ताइवान को बेचे जाने वाले हथियारों पर लगाई रोक

वाशिंगटन। ईरान एवं अमेरिका के बीच जारी तनाव के कारण अमेरिका ने ताइवान को बेचे जाने वाले 14 अरब डॉलर के हथियारों के सौदे पर फिलहाल रोक लगा दी है।

■ ईरान एवं अमेरिका के बीच जारी तनाव के कारण के चलते वाशिंगटन का अहम फैसला

की है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है, जब कुछ ही दिनों पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई थी। इस बैठक के बाद ट्रम्प ने ताइवान को हथियारों की बिक्री पर कोई टोस प्रतिबद्धता नहीं दिखाई थी। महीनों से राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार कर रहे इस भारी-भरकम सुरक्षा पैकेज में लोकहीड मार्टिन के पीएस-3 एयर डिफेंस मिसाइल और सतह से हवा में मार करने वाली आधुनिक मिसाइल प्रणालियां शामिल हैं। दूसरी ओर, इस बड़े फैसले से ताइवान पूरी तरह अनजान नजर आ रहा है।

भारत-साइप्रस ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का रूप दिया

दोनों देशों में सहमति बनी है, साइप्रस भारत में निवेश को दोगुना करेगा: प्रधानमंत्री

■ दोनों देशों ने साइबर और समुद्री सुरक्षा तथा आतंकवाद रोधी सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है: पीएम



■ भारत और साइप्रस ने शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भी समझौते किए हैं

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि साइप्रस भारत और समूचे यूरोप के बीच एक महत्वपूर्ण 'निवेश द्वार' के रूप में उभर रहा है और इसे देखते हुए हमने अपने संबंधों को सामरिक साझेदारी में बदलकर संबंधों को सहयोग से सह-निर्माण तक, और साइबरी से साक्षात् समुद्र तक ले जाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों में सहमति बनी है कि साइप्रस भारत में निवेश को दोगुना करेगा।

उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने साइबर और समुद्री सुरक्षा तथा आतंकवाद रोधी सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में सुधार को जरूरत पर भी बल दिया है। साथ ही भारत और साइप्रस ने शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भी समझौते किए हैं। दोनों पक्षों ने हिन्दू प्रशांत महासागर और भारत-पश्चिम एशिया यूरोप

आर्थिक गलियारों जैसी महत्वपूर्ण पहलों के माध्यम से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की है। मोदी ने भारत की तीन दिन की यात्रा पर आए साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स के साथ शुक्रवार को यहां द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में यह बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में, साइप्रस से भारत में निवेश बचकर लगभग दोगुना

हो गया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच विश्वास बढ़ने और भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसका लाभ उठाते हुए कि हम अगले पांच वर्षों में इस निवेश को फिर से दोगुना करने का लक्ष्य रख रहे हैं। और इस संकल्प को साकार करने के लिए, आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक रणनीतिक साझेदारी का रूप दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत और साइप्रस के

बीच यह साझेदारी दोनों देशों के वित्तीय और सेवाओं को जोड़कर, वाणिज्य के लिए पूंजी लाएगी। यह साइप्रस के अवसर, ऊर्जा, और कृषि क्षेत्र में भारतीय कंपनियों के लिए नए अवसर प्रदान करेगी। इससे भारत के तेजी से बढ़ रहे नौवहन और समुद्री क्षेत्रों में नया निवेश भी आएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम साइप्रस के साथ मिलकर, गिफ्ट सिटी को एक ग्लोबल फाइनेन्शियल और सर्विसे हब बनाने के विद्यन को गति देंगे। और दोनों देशों के इन्वैशन और स्टार्ट-अप एकोसिस्टम के बीच कनेक्ट बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी संबंधों का एक महत्वपूर्ण स्तम्भ है। उन्होंने कहा कि हमें बहुत खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच मिलितरी एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़े हैं। आज हमने साइबर सिक्युरिटी, मैरीटाइम सिक्युरिटी और काउन्टर-टेरिस्ट सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया।

शेख हसीना कानूनी प्रक्रिया से वापस लौटें: बांग्लादेश

ढाका। बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने कहा है कि सरकार पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से वापस लाना चाहती है। यह टिप्पणी हसीना की हालिया बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने मृत्युदंड का सामना करने के बावजूद बहुत जल्द घर लौटने की उम्मीद जताई थी। हसीना अगस्त 2024 से भारत में रह रही हैं, जब छात्र-नेतृत्व वाले विद्रोह के बाद उनकी अवांमनी लीग सरकार को गिरा दिया गया था। अहमद ने पत्रकारों से कहा, हम उन्हें कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से वापस लाना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें हसीना की वापसी में कोई कानूनी बाधा नहीं दिखती, यदि वह ऐसा करना चाहें। हसीना को नवम्बर 2025 में एक न्यायाधिकरण द्वारा अनुपस्थिति में मृत्युदंड सुनाया गया था, जिसकी उनके समर्थकों ने आलोचना की थी। गृह मंत्री अहमद को यह टिप्पणी प्रधानमंत्री तारिक रहमान के सूचना मामलों के सलाहकार जाहेदुर रहमान के बयान के एक दिन बाद आई है। जाहेदुर रहमान ने कहा था कि यदि हसीना बांग्लादेश लौटती हैं तो उनके खिलाफ कोई अतिरिक्त-न्यायिक उपाय नहीं किए जाएंगे। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि पूर्व प्रधानमंत्री को न्यायपालिका के सामने आत्मसमर्पण करना होगा।

होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों से फीस वसूलेगा ईरान

तेहरान। ईरान और ओमान होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर फीस वसूली के सिस्टम को लेकर बातचीत कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की नई बनाई गई पर्सियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी (पीजीएसए) ने कहा कि उसने होर्मुज स्ट्रेट के 'मैनैजमेंट सुपरविजन एरिया' की सीमा तय कर दी है। अथॉरिटी के मुताबिक, यहां से गुजरने के लिए परमिट जरूरी होगा। फरवरी में अमेरिकी और इजरायली हमलों के बाद ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में कमर्शियल ट्रेडिक लाभांश रोक दिया था। इससे अंतरराष्ट्रीय शिपिंग प्रभावित हुई और ऊर्जा कीमतों में भी आइ। इसके बाद ईरानी अधिकारियों ने इस जलमार्ग से राजस्व जुटाने के विचारों पर चर्चा शुरू की।

ओमान के साथ पेमेंट सिस्टम पर बातचीत जारी, होर्मुज स्ट्रेट के नैजैजमेंट सुपरविजन एरिया की सीमा तय कर दी है: पीजीएसए



■ दुनिया के करीब 20 प्रतिशत समुद्री तेल और प्राकृतिक गैस की सप्लाई होर्मुज स्ट्रेट से गुजरती है

देश पर हमला अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। बचाई ने कहा कि फरवरी के अंत में ईरान पर हुआ अमेरिका-इजरायल हमला और उसके बाद का युद्ध संयुक्त राष्ट्र चार्टर का खुला उल्लंघन है। उनके मुताबिक, संयुक्त राष्ट्र चार्टर किसी भी देश को मनमाने तरीके से दूसरे संप्रभु राष्ट्र पर बल प्रयोग का अधिकार नहीं देता। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर में 'आवश्यक युद्ध' जैसी किसी अवधारणा को मान्यता नहीं दी गई है और अमेरिका अपने 'मनमाने और आक्रामक फैसलों' के आधार पर किसी अन्य देश पर हमला करने का अधिकार नहीं ले सकता। ईरानी प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका-इजरायल हमले को केवल 'आवश्यक युद्ध' कहकर कमतर नहीं आका जा सकता। उन्होंने इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2(4) का स्पष्ट उल्लंघन और 'संप्रभु राष्ट्र के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई' बताया। बचाई ने कहा कि जो देश कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का सम्मान करते हैं, उन्हें इस हमले की स्पष्ट निंदा करनी चाहिए और जवाबदेही तय करने की मांग करनी चाहिए। ईरान को इस्लामिक रिवायल्यूशनरी गार्ड क्राफ्स (आईआरजीसी) नौसेना ने दावा किया है कि पिछले 24 घंटों में 35 जहाज, जिनमें तेल टैंकर और कंटेनर पोत शामिल हैं, होर्मुज स्ट्रेट से गुजरे। आईआरजीसी ने कहा कि यह आवाजाही उसकी अनुमति और समन्वय से हुई।



वाराणसी। बकरीद (ईद-उल-अजहा) के त्योहार से पहले पशु बाजार में बकरा खरीदने के बाद उसको गोद में उठाकर ले जाता एक बच्चा।

होर्मुज में शुल्क लगाने की व्यवस्था को स्वीकार न करे विश्व समुदाय: अमेरिका

हेल्सिंगबर्ग (स्वीडन)। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने शुक्रवार को कहा कि संघर्ष रोकने के लिए ईरान के साथ जारी बातचीत में थोड़ी प्रगति हुई है। हालांकि, उन्होंने एक बार फिर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के सहयोगियों के रुख नारा जमा जताई। रुबियो ने स्वीडन में नाटो के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा, वार्ता में मामूली प्रगति हुई है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नाटो सहयोगियों के रुख को लेकर निराश हैं। हेल्सिंगबर्ग में प्रेस कान्फ्रेंस के दौरान रुबियो ने कुछ मामूली प्रगति हुई है। मैं इसे बढ़ा-चढ़ाकर नहीं बताना चाहता। थोड़ी हलचल जरूर हुई है और यह अच्छा बात है। अमेरिका की मुख्य रणनीतिक मांगों पर रुबियो ने कहा कि वाशिंगटन का रुख अब भी साफ है। अमेरिका चाहता है कि तेहरान अपनी परमाणु महत्वकांक्षाएं रोकें और बिना बाधा के समुद्री मार्गों पर आवाजाही जारी रहे।

हमजा बुरहान की हत्या का आरोपी हथियार समेत गिरफ्तार

इस्लामाबाद। पुलवामा हमले में शामिल आतंकी हमजा बुरहान की हत्या के मामले में मुजफ्फराबाद के काउंटर टेरिज्म डियाटमेंट (सीटीडी) ने अब्दुल्ला कमाल नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। अब्दुल्ला कमाल पाकिस्तान के वाह कैंट का रहने वाला है। कार्रवाई के दौरान आरोपी के पास से हथियार भी बरामद किया गया। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि हत्या में इसी हथियार का इस्तेमाल हुआ था या नहीं। दो अन्य संदिग्धों के से भाग निकले। आरोपी अब्दुल्ला कमाल की फोटो

दो संदिग्ध फरार

पुलवामा हमले में शामिल था बुरहान, इस्लामाबाद में दफनाया गया

भी सामने आई है। हमजा बुरहान 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में शामिल था। जिसमें सीआरपीएफ काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें 40 जवान शहीद हुए थे। हमजा बुरहान को इस्लामाबाद के फातिमा स्कूल में दफनाया गया। भारत ने 2022 में उसे यूएपीए के तहत आतंकी घोषित किया था। वह अब दुजाना, अबू कासिम, बुरहान बानी और जाकिर मूसा का करीबी सहयोगी माना जाता था। उसके पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से भी करीबी संबंध थे। सरकार के मुताबिक, अर्जुमंद गुलजार डार उर्फ हमजा बुरहान उर्फ डाक्टर पुलवामा के रत्नीपोरा इलाके का रहने वाला था। 23 साल का हमजा, आतंकी संगठन अल बद्र से जुड़ा हुआ था। अल बद्र को सरकार ने आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। वह कानूनी तरीके से पाकिस्तान गया था। वहां जाकर वह अल बद्र में शामिल हो गया और बाद में संगठन का सक्रिय आतंकी और कमांडर बन गया।

ईरान कर सकता है अचानक इजरायल पर हमला

तेल अवीव। इजरायल को अदेश है कि ईरान उस पर और खाड़ी देशों पर अचानक मिसाइल और ड्रोन से हमला कर सकता है। यह डर ऐसे समय में जताया गया है जब अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर को लेकर पदों के पीछे बातचीत चल रही है। 'जेरुसलम पोस्ट' की एक रिपोर्ट के अनुसार, खुफिया अधिकारियों ने इस संभावित खतरे की जानकारी दी है। इस खतरे को देखते हुए इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काटज और वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने सुरक्षा हालात को समीक्षा की है। सुरक्षा अधिकारियों का मानना है कि ईरान कूटनीतिक कोशिशों के पूरी तरह नाकाम होने से पहले ही हमला करने की कोशिश कर सकता

अमेरिका-ईरान के बीच सीजफायर को लेकर चल रही बातचीत के बीच खौफ में नेतन्याहू

है। अधिकारियों ने इस संभावित हमले की तुलना 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' और 'ऑपरेशन रॉसिंग लायन' के शुरुआती चरणों से की है। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच कुछ मतभेदों की खबरें भी आई हैं। इसके बावजूद, दोनों देशों की सेनाएं किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। इजरायली वायुसेना और आईडीएफ के अधिकारी अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वे ईरान की संदिग्ध सैन्य गतिविधियों पर नजर रखने के लिए खुफिया जानकारी साझा कर रहे हैं। लैपटॉप जनरल इयाल जमीर लगातार अमेरिकी अधिकारियों के संपर्क में हैं ताकि हमले की स्थिति में मिलकर जवाब दिया जा सके। पिछले एक महीने में अमेरिका से इजरायल आने वाले सैन्य सामान की सप्लाई में काफी तेजी आई है। दोनों देशों ने मिलकर मिसाइलों को रोकने वाले सिस्टम, तकनीक और साफ्टवेयर को ओर भी बेहतर बनाया है। श्वल्लार की एक रिपोर्ट के अनुसार, खतरों की पहचान करने और उन्हें हवा में ही नष्ट करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए एक व्यापक समीक्षा की गई है।

होंडुरास में छह पुलिसकर्मियों समेत 25 लोगों की हत्या

टुजिलो नगर। मध्य अमेरिकी देश होंडुरास से एक बेहद खौफनाक और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां हथियारबंद बदमाशों ने दो अलग-अलग जगहों पर अंधाधुंध गोलीबारी की है। इस भयानक हमले में कम से कम 25 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। मरने वालों में पुलिस के छह जवान भी शामिल हैं। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। यह खूनी खेल गुरुवार को होंडुरास के तटीय इलाकों में खेला गया। अधिकारियों के मुताबिक, पहला हमला उत्तरी होंडुरास के टुजिलो नगर पालिका क्षेत्र के एक बागान में हुआ। यहां काम कर रहे कम से कम 19 मजदूरों को गोलीबारी से भून दिया गया। इसके बाद दूसरा हमला ग्वाटेमाला सीमा के पास ओमोआ इलाके में हुआ, जहां बदमाशों ने पुलिस टीम पर घात लगाकर हमला कर दिया। इस हमले में एक वरिष्ठ अधिकारी समेत छह पुलिसकर्मियों की जान चली गई। टुजिलो का इलाका प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है और यहां दशकों से जमीन और खेती को लेकर खूनी संघर्ष चलता आ रहा है।

यौन समस्याएं

यौन समस्याओं के विशेषज्ञ

पुराने से पुराने यौन रोग के मरीज एक बार अवश्य मिलें

डा. सम्राट

नशामुक्ति, शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा तम्बाकू, प्रोक्सीवॉन कैप्सूल, अफीम, चरस, डोडे पोस्टा इंजेक्शन व अन्य नशा छुड़ाने का स्थायी ईलाज।

नावल्टी सिनेमा चौक मुजफ्फरनगर (यू.पी.)

M-9412211108

RADHA KRISHNA SR. SEC. PUBLIC SCHOOL, AMROHA

Affiliated to CBSE Delhi | Affiliation No. : 2130347

HIGHLIGHTS OF CBSE RESULT CLASS X & XII (2025-26)

Our Achievers

CLASS X					CLASS XII					
98%	97%	94%	93%	92%	96%	96%	93%	93%	92%	92%
Commerce	Science	Science	Science	Science	Commerce	Science	Science	Science	Commerce	Science
91%	91%	90%	90%		92%	92%	92%	91%	91%	
Science	Science	Science	Science		Science	Science	Science	Commerce	Humanities	

CLASS XII ACHIEVERS

Student's Scored 90+ in English	Student's Scored 90+ in Maths	Student's Scored 90+ in B. Studies	Student's Scored 90+ in Chemistry
Shreyanshi (99), Dhairya Agarwal (96)	Anishant (92), Kartik Chauhan (91)	Kanika Saini (96), Siya Gera (94)	Jatin Rana (97), Kartik Chauhan (95)
Dhairya Chaudhary (96), Jatin Rana (95)	Student's Scored 90+ in Accountancy	Student's Scored 90+ in IP	Mayank Chaudhary (95), Tushar Sirohi (95), Daksh Kumar (93)
Kanika Saini (95), Mayank Chaudhary (94)	Siya Gera (94), Zaib Noor (94), Aryan Kumar (92)	Jatin Rana (99), Kanika Saini (94)	Student's Scored 90+ in Biology
Emira Hashmi (92), Fareha (92), Kartik Chauhan (92)	Kanika Saini (96), Shivi Agarwal (95)	Vedant Gupta (94)	Daksh Kumar (99),
Anushka Verma (92), Amrita (92), Sabiha (91), Tushar (91)	Siya Gera (94)	Aryan Kumar (91)	
Anshika Yadav (90), Parth Saxena (90), Daksh Kumar (90)			

Address : Kailsa Road Amroha - 244221 (U.P.) Call : 09837097452, 09837127111

E-Mail : rkpschool@gmail.com https://www.facebook.com/RkpsSchoolAmroha www.rkpschool.com